लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2769
18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विद्युतकरघा श्रमिकों का कल्याण

2769. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विद्युतकरघा श्रमिकों के कल्याण के लिए और विशेषकर उनके बच्चों की शिक्षा और घरेलू कल्याण योजनाओं तक पहुंच को बढ़ाने के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को वस्त्र श्रमिकों के लिए अलग कल्याण बोर्ड के गठन पर कोई आपत्ति है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विद्युतकरघा श्रमिकों के लिए पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए किन विशिष्ट उपायों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग): भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से, पावरलूम कामगारों के कल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों को लागू कर रही है, जिसमें उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को पहुँच शामिल है। पावरलूम कामगारों के लिए समूह बीमा योजना (जीआईएस) 1 जुलाई 2003 को शुरू की गई थी और पावरलूम क्षेत्र के कामगारों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए संशोधनों के साथ वर्ष 2019-20 तक बढ़ा दी गई थी। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत नामांकित कामगार शिक्षा सहयोग योजना (एसएसवाई) के तहत प्रति वर्ष प्रति बच्चे को 1,200 रुपए के शैक्षिक अनुदान के लिए पात्र हैं, जिसका लाभ चार वर्ष तक कक्षा IX से XII तक अध्ययन करने वाले अधिकतम दो बच्चों को मिलता है। केवल जीवन और दुर्घटना बीमा लाभों को देने के लिए वर्ष 2017 से, जीआईएस को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ एकीकृत किया गया है।

भारत सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) भी शुरू की, जो पावरलूम कामगारों सहित पात्र असंगठित क्षेत्र के कामगारों को योजना दिशानिर्देशों के अधीन 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है।

***